राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 14.02.2014 को आयोजित 120वीं बैठक के कार्यवृत

बैठक की अध्यक्षता श्री पी.श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गई। बैठक में डॉ.राजेन्द्र कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक , नाबार्ड, डॉ.सत्येन डेविड,क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक,श्री सिद्धार्थ महाजन,विशेष सचिव(वित्त) राजस्थान सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारिगण, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों द्वारा सहभागिता की गई। (सूची संलग्न है)

श्री एल.एम.अस्थाना, संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय से उनके उदबोधन हेतु आग्रह किया गया।

श्री पी.श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए बताया कि राज्य में साख-जमा अनुपात उच्च रहते हुए 93.11% रहा, जो राज्य में उत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है । उन्होंने बताया कि राज्य मे कार्यरत बैंकों द्वारा विभिन्न पैरामीटर्स तहत संतोषप्रद उपलब्धि दर्ज की गई है।

वार्षिक साख योजना के तहत उपलब्धि 88% रही। दिसम्बर, 2013 को राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि तथा कमजोर वर्ग को प्रदत्त अग्रिमों का स्तर निर्धारित बैंचमार्क से कहीं अधिक रहा।

उन्होने राज्य मे कृषि ऋणों में वृद्धि हेतु अपार सम्भावनाये बतायी तथा एग्रीकल्चर इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट जैसे Soil & Water Conservation, Horticulture Plantation,Post Harvest Activities हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता बतायी व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को Rupay Card शीघ्र जारी करने पर बल दिया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) स्कीम के क्रियांवयन हेतु चिन्हित जिलों यथा अजमेर,अलवर,उदयपुर,झुंझुनू, कोटा तथा पाली मे कार्यरत सभी शाखाओं मे शीघ्रतिशीघ्र ए.टी.एम.स्थापित किये जाने तथा DBT जिलों मे आंवटित अंबैक्ट एस.एस.ए.(Unbanked SSAs) मे बैकिंग आउटलेट स्थापित करने के लिये तत्परता से कार्य किये जाने पर बल दिया गया ।

सदन को अवगत करवाया कि वर्तमान मे राज्य मे 23 जिलों मे DBTL योजना लागू है ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी अनकवर्ड SSAs (Uncovered SSAs) को मार्च 2014 तक कवर किये जाने पर बल दिया ।

राज्य मे स्थापित सभी शाखाओं के On Site ATM स्थापित करने के 100% लक्ष्य को मार्च,14 तक पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में राज्य में कार्यरत्त बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज का अच्छा कार्य किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के गठन, बैंक लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज सततरुप से करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने राजस्थान के अलवर,अजमेर,दौसा तथा उदयपुर जिलो को NRLM के प्रथम चरण मे

NRLM योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को रु.300000/- तक का ऋण 7% ब्याज पर उपलब्ध करवाने तथा Prompt Repayment पर 3% के अतिरिक्त अनुदान के सम्बन्ध मे सूचित किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सरकारी योजनाओं के तहत दिनांक 31.01.14 तक प्राप्त आवेदन पत्रो का निस्तारण 28.02.14 तक किया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये जोर दिया । अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों को कारण सहित प्रायोजित करने वाली एजेंसी को तुरंत लौटाने के लिये सभी बैंकों से आग्रह किया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ओर प्रयास किए जाने तथा Minority Concentrated Blocks मे स्थित बैक शाखाओं को विशेष लक्ष्य आवंटित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

राज्य मे बडी संख्या मे बकाया **RODA Cases** के मध्यनजर सरकारी विभागों को वसूली मे बैकों को सहयोग देने पर बल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्धि की समीक्षा एवं अन्य विकासपरक मुद्दों पर आज की बैठक के कार्यसूची में विस्तृत चर्चा की जावेगी। अंत में उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

तत्पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1)</u> सदन द्वारा विगत 119 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

(i) **To facilitate banks to create online charge on agriculture land for extending agriculture credit to farmers** :-
कृषि भूमि पर बैंक का प्रभार ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा बैंकों को उपलब्ध करवाने हेतु राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से पुन: अनुरोध किया गया ।

<u>(कार्यवाही: राजस्व विभाग)</u>

(ii) **Setting up of brick & mortar branch/6days ultra small branch in all FI villages having population>5000 in under banker district & > 10000 in other district-** सदन को अवगत करवाया गया कि शाखाएं/6 Days USB खोलने के लिये 138 गांवो को चिन्हित किया गया है जिनमे से 137 केन्द्रो पर शाखाएं/6 Days USB खोल दी गई है । शेष रहे -1- केन्द्र पर शाखा/6 Days USB खोलने के बारे मे SBBJ को आवश्यक कदम उठाना है ।
श्री जे.के.बागडी, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, ने SBBJ को शेष रहे -1- केन्द्र को शीघ्र कवर करने पर बल दिया ।

(iii) Sub Service Area Approach- Mapping of Gram Panchayat for coverage

through Branch/BCA/CSC :Banks to ensure coverage of all unbanked sub service area (SSA)

राज्य की सभी 9091 ग्राम पंचायत में 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) चिन्हित किए गए है,जिनमें से 5438 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) बैंक शाखा/बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा चुके है।

बैंको को आवंटित शेष 3968 unbanked SSAs को शीघ्र कवर करने का आग्रह किया गया तथा इसमे DBT जिलों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(iv) Installation of Onsite ATM:

राज्य मे कार्यरत 5889 शाखाओं मे से 3131 शाखाओं मे onsite 3131 ATM है।

अध्यक्ष महोदय ने शेष रही शाखाओं के 31.03.14 तक Onsite ATM स्थापित करने के लिये सभी बैकों को आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(vi) Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

वित्त/राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2:</u>

शाखा विस्तार: राज्य में 31.12.2013 को कुल 5988 बैंक शाखाएँ कार्यरत्त है। चालू वित्त वर्ष के दौरान खोली गई 255 शाखाओं में से 215 (84%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गई।

जमाएँ व अग्रिम: दिसम्बर,2013 को राज्य में कुल जमाएँ रूपये 205347 करोड़ तथा कुल अग्रिम रूपये 184733 करोड़ रहा ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: कुल **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को ऋण रूपये 101297 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम का 54.83% रहा । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में YOY वृद्धि 22.26% रही। वहीं कृषि में 19.55%, सूक्ष्म व लघु क्षेत्र एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 25.86% रही

राज्य मे कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 30.63%, कमजोर वर्ग को 16.84% तथा **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को पदत कुल ऋणो का अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण 6.43% रहा ।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा इन क्षेत्रो को प्रदान किये जाने वाले अग्रिमो के लिये निर्धारित Norms के पेटे(Against) उपलब्धि के आंकडे दर्शाने का सुझाव दिया गया।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): दिसम्बर, 2013 को राज्य में साख जमा अनुपात 93.11% रहा। जिला स्तर पर 31 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से अधिक रहा, वहीं दो जिलों यथा डूंगरपुर व राजसमन्द में यह अनुपात 50% 50% से नीचे रहा है।

मुख्य महाप्रबन्धक , नाबार्ड तथा महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन दो जिलो मे साख जमा अनुपात मे वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वार्षिक साख योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों(वार्षिक) के सापेक्ष दिसम्बर तक उपलब्धि 88% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 86%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 162%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 49% की उपलब्धि दर्ज की गई।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि कृषि क्षेत्र मे रिपोर्टिंग फार्मेट को अल्पावधि ऋण, दीर्घावधि ऋण में वर्गीकृत किया जाये जिससे कि समुचित रुप मे निगरानी की जा सके।

महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शिक्षा व आवास ऋण को वार्षिक साख योजना की उपलब्धि मे शामिल किये जाने का सुझाव दिया गया ।

एजेण्डा क्रमांक – 3-

To open branch/6days ultra small branch in villages with population 5000 & above in under banked district & 10000 & above in other district-

सदन को अवगत करवाया गया कि शाखाएं/6 Days USB खोलने के लिये 138 केन्द्रो को चिन्हित किया गया है जिनमे:

- Under Banked District के 5000 व अधिक जनसंख्या वाले 136 केन्द्र तथा,
- अन्य जिलों के 10000 व अधिक जनसंख्या वाले -2- केन्द्र चिन्हित किये गये ।

इनमे से 137 केन्द्रो पर शाखाएं/6 Days USB खोल दी गई है । शेष रहे -1- केन्द्र (Kachroli District Karauli) पर शाखाएं/6 Days USB खोलने के बारे मे SBBJ को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गयी ।

महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि चिन्हित किये गये केन्द्र पर सम्बन्धित बैक द्वारा बैकिंग आउटलेट स्थापित नही किये जाने को गम्भीरता से लिया जायेगा ।

(कार्यवाही: एस.बी.बी.जे.)

Direct Benefit Transfer (DBT)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अनुरोध किया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की **DBT** स्कीम के तहत चिन्हित 6 जिलो यथा अजमेर,अलवर,उदयपुर,झुंझुनू,कोटा तथा पाली मे चिन्हित लाभार्थियों के खाते खोले व खाता धारकों के बैंक खातों में आधार नम्बर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की **DBT** स्कीम के तहत राज्य मे दौसा,सीकर,जयपुर,राजसमन्द,सिरोही तथा चुरु को अगले चरण के लिये चिन्हित किये गये है ।

Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा DBTL योजना के क्रियांवयन के लिये राज्य सरकार/नोडल विभाग द्वारा लाभार्थियों की सूची आवश्यक जानकारी यथा बैंक खाता नम्बर,आधार सीडिंग इत्यादि उपलब्ध करवाने

का अनुरोध किया गया, जिससे बैक खाते मे आधार सीडिंग किया जाकर DBTL का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

मिशन डायरेक्टर(DBT) योजना आयोग,भारत सरकार द्वारा संयोजक, एस.एल.बी.सी के साथ DBTL योजना तहत प्रगति की नियमित रुप से समीक्षा की जाती है । पिछली समीक्षा बैठक दिनांक 28.01.14 के दौरान निम्नलिखित मुद्धे उभरकर आये :-

* बैकों को आवंटित SSAs को मार्च,2015 तक कवर किया जाये तथा DBT जिलों मे इन्हे शीघ्रातिशीघ्र कवर किया जाये ।
* सभी शाखाओं के ऑन-साइट ए.टी.एम. स्थापित किये जाये ।
* Phase-III तथा IV तहत चिन्हित DBTL जिलों मे आधार सीडिंग का 50% लक्ष्य 15.02.14 तक प्राप्त किया जाये ।
* बचत व बेसिक बचत बैक खाताधारको को डेबिट कार्ड जारी किये जाये ।

DBT तथा DBTL की प्रगति व आधार सीडिंग तथा खाते खोलने के सम्बन्ध मे प्रगति की समीक्षा व फीडबैक लेने के लिये OMCs, अग्रणी जिला प्रबन्धकों तथा DCC समंवयक बैको के नियंत्रको की दिनांक 10.01.14 को SLBC द्वारा जयपुर मे बैठक आयोजित की गयी जिसमे प्रमुख निम्न बाते उभरकर सामने आयी:-

अग्रणी जिला प्रबन्धकों ने विचार प्रकट किया कि बैंक खाते मे आधार सीडिंग से सम्बन्धित Annexure-I ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा बैको व LPG ग्राहको को उपलब्ध नही करवाया जा रहा है, जिन मामलों मे प्राप्त किया जाता है उन्हें भी अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उपलब्ध नही करवाया जाता ।

LPG ग्राहको को अनुदान नही मिलने सम्बन्धी शिकायतों को भी बैको/ अग्रणी जिला प्रबन्धकों को ही divert किया जा रहा है ।

वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार SLBC संयोजक बैक के कार्यकारी निदेशक द्वारा DBTL के अन्य हितधारको के साथ दिनांक 25.10.13 को अजमेर मे तथा SLBC संयोजक बैक के कॉरपोरेट महाप्रबन्धक द्वारा झुनझुनू तथा चुरु मे 23 व 24.01.14 को बैठक आयोजित कर योजना तहत प्रगति की समीक्षा की गयी ।

Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSCs for Direct Cash Transfer – Sub Service Area Approach:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सदन को अवगत करवाया कि MOF GOI के निर्देशानुसार जनसंख्या व दूरी के आधार पर राज्य मे कुल 9091 ग्राम पंचायतों मे 9406 SSAs चिन्हित किये गये है तथा बैकों को आवंटित किये गये है। जिनमे से 5438 SSAs अब तक कवर किये जा चुके है

- संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अनुरोध किया गया है कि शेष रहे SSA मे भी अतिशीघ्र बैकिंग आउटलेट (शाखा/कियोस्क/मोबाइल वैन इत्यादि) स्थापित करने की कार्यवाही की जाये ।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

Development of MIS reporting System for creation of SSAs and monitoring progress in extension of banking facilities in the SSAs:

MOF GOI द्वारा SSA की पुर्ण जानकारी हेतु **MIS** पोर्टल विकसित किया गया है । प्रथम चरण मे PILOT आधार पर अग्रणी जिला उदयपुर को इस पोर्टल पर SSA की सुचनाये अद्धतन करने हेतु चिन्हित किया गया । अब सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको को SSA की सुचनाये अधतन करने हेतु यह पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है।

अग्रणी जिला प्रबन्धक दौसा,नागौर,बाडमेर,सिरोही तथा सीकर को छोडकर सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा **MIS** पोर्टल पर डाटा अद्दतन (अपडेशन) कर लिये जाने से सूचित किया है। बैठक मे इन अग्रणी जिला प्रबन्धको के नियंत्रक बैकों द्वारा डाटा शीघ्र अद्दतन किये जाने के लिये आश्वस्त किया गया ।

Roadmap for providing banking services in villages<2000 -

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस विषय मे हुई प्रगति कि जानकारी सदन को दी गयी :-
2000 से कम आबादी वाले 35085 गांवो मे से चालू वित्त वर्ष के 6867 गांवो को कवर करने के लक्ष्यो के पेटे दिसम्बर,13 तक 8770 गांवों को कवर किया जाना से अवगत करवाया गया।

मुख्य महाप्रबन्धक ,भारतीय रिजर्व बैंक ने बैकों को BCs के कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये कहा जिससे कि ग्रामवासियों को बैकिंग सवाओं का लाभ निर्बाध रुप से गांव मे ही प्राप्त हो सके ।

उन्होंने बताया कि बैकों के नियंत्रकों(Controllers) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वित्तीय समावेशन के तहत खोले गये बचत खातों मे निर्धारित अधिविकर्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ।

Urban Financial Inclusion:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा रुरल वित्तीय समावेशन की तरह अरबन वित्तीय समावेशन पर कार्य किये जाने बल दिया गया व शहरी गरीब, विस्थापित व्यक्तियों इत्यादि को बैकिंग सेवा के दायरे मे लाने हेतु अरबन कियोस्क स्थापित करने जैसी कार्यवाही की जाये ।

Uploading of GIS data:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि GIS Portal पर बैंकों से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी यथा नई शाखा/करेंसी चेस्ट, नियुक्त बीसी. एजेण्ट, नए स्थापित ए.टी.एम. इत्यादि अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा अपडेट रखनी है। नियमित अपडेशन के लिये जिले मे स्थित सभी बैको द्वारा उक्त जानकारियां अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करवाया जाना अहम है।

डी.सी.सी. संयोजक बैंक से अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा GIS Portal पर मासिक आधार पर सूचनाओं को अद्यतन करवाना सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

एजेण्डा क्रमांक – 4:

Agriculture Credit Flow: वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दिसम्बर, 2013 को राज्य मे कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 30.63% रहा ।

अध्यक्ष महोदय ने राज्य मे कृषि ऋणों में वृद्धि हेतु अपार सम्भावनाये बतायी तथा एग्रीकल्चर इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट जैसे Soil & Water Conservation, Horticulture Plantation,Post Harvest Activities हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता बतायी व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को डेबिट कार्ड/ए.टी.एम कार्ड शीघ्र जारी करने पर बल दिया ।

ग्रामीण भण्डारण योजना :

सदन को अवगत करवाया गया कि नाबार्ड के परिपत्र दिनांक 23.08.13 के अनुसार कॉमन वाल (Common Wall) के साथ निर्मित गोदाम भी इस योजना तहत अनुदान के योग्य होंगे।

Union Budget-2013-14: Interest Subvention Scheme:

सदन को सूचित किया गया कि Interest Subvention Scheme का लाभ अब निजी क्षेत्र के कॉमर्शियल बैकों को भी उपलब्ध है ।

मुख्य महाप्रबन्धक,नाबार्ड ने कृषिगत गतिविधियों- अल्पकालिन/दीर्घकालिन ऋण के बकाया शेष से सम्बद्ध जानकारी भी प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाये.

GOR Interest subvention Scheme for KCC holders of Cooperative Banks:

योजनांतर्गत सहकारी बैकों द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले रु.1.50 लाख तक के अल्पावधि फसली ऋणों पर राज्य सरकार 4% Interest subvention उपलब्ध करवा रही है ।

एस.एल.बी.सी तथा नाबार्ड के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार से पुनः आग्रह किया गया कि यह लाभ अन्य बैकों तथा वित्तीय संस्थानों के के.सी.सी.धारको को भी उपलब्ध करवाया जाये । इस पर विशेष सचिव (वित्त) राजस्थान सरकार ने मामले को उचित स्तर पर विचारार्थ रखने का आश्वासन दिया ।

Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme for Farmer Producer Companies"(EGCGFS) to promote and strengthen farmer producer Organisation(FGPOs):

SFAC नई दिल्ली के प्रतिनिधि श्री आर.पी.शर्मा ने केन्द्रीय बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा लांच की गयी "Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme for Farmer Producer Companies" to promote and strengthen farmer producer Organisation(FGPOs) पर प्रकाश डाला ।

श्री शर्मा ने बताया कि क्रेडिट गारण्टी फण्ड(CGF) तहत कवर प्राप्त करने के लिये सभी बैक योग्य(Eligible) है ।

मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड ने विस्तृत स्कीम नाबार्ड को प्रेषित किये जाने का आग्रह किया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 5:Government Sponsored Schemes:</u>

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): योजना अंतर्गत 2013-14 के लिए 8000 लाभार्थियो को लाभांवित करने के लक्ष्य बैको को दिया गया है,जिसके तहत दिसम्बर,13 तक कुल 2386 मे स्वीकृत्तियां जारी की गयी जो कुल लक्ष्यों की 29.82% रही तथा 1290 मे ऋण वितरण किया गया ।

परियोजना निदेशक (SJSRY) ने लम्बित आवेदन पत्र के शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया ।

Special Central Assistance Scheme SC/ST (POP)-

योजना अंतर्गत 2013-14 तहत दिसम्बर तक कुल 6887 स्वीकृतिया जारी की गयी जो कुल लक्ष्यो 30620 की 22.49% रही।

Central Sector Schemes of Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS)- Revision of Scheme :

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा संशोधित योजना की जानकारी दी तथा तहत पात्र लाभार्थियों को लाभांवित किये जाने का आग्रह किया गया ।

प्रधामंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): सदन को अवगत करवाया गया कि योजना अंतर्गत 2013-14 तहत दिसम्बर तक कुल 772 मे स्वीकृतिया जारी की गयी जो कुल लक्ष्यो की 31.80% रही ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सरकारी योजनाओं की प्रायोजित एजेंसियो से आंवटित लक्ष्यों के मध्यनजर क्षेत्रवार/जिलेवार पर्याप्त आवेदन पत्र प्रायोजित किये जाने हेतु आग्रह किया तथा प्राप्त आवेदन पत्रो को शीघ्रता से निस्तारित करने के लिये बैकों को निर्देशित किया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा PMEGP तहत प्राप्त सभी आवेदन पत्रो के निस्तारण सम्बन्धी विवरण e-tracking portal पर Update रखने हेतु बैकों से अनुरोध किया ।

Self Help Groups (SHG): सदन को अवगत करवाया गया कि दिसम्बर तक राज्य में 9684 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज से तथा 5751 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है। SHG बैंक/क्रेडिट लिंकेज हेतु अनुमोदित Common आवेदन पत्र एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है।

भारत सरकार की पिछड़े जिलों यथा बाडमेर,बांसवाडा,डूंगरपुर,झालावाड में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन योजना के तहत राज्य में वर्ष 2013-14 के लिये 3600 SHGs का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । दिसम्बर,2013 तक कुल 2805 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा 2170 समूहों का बैंक लिंकेज किया गया है।

सदन को अवगत करवाया गया कि **2013-14 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग** द्वारा राज्य मे महिला स्वयं सहायता समूह के लिये राज्य मे संचालित 50% ब्याज अनुदान व एक मुश्त अनुदान योजना के तहत चालू वर्ष के दौरान वित्त पोषित महिला स्वयं सहायता समूह के योजनानुसार अनुदान क्लेम सम्बन्धित नोडल शाखा को तुरंत प्रस्तुत किये जाने चाहिये जिससे कि योजना अंतर्गत हुई प्रगति परिलक्षित हो सके ।

मुख्य महाप्रबन्धक , नाबार्ड द्वारा अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज से जोडने का आग्रह किया गया ।

Credit Flow to Minority Community: सदन को अवगत करवाया गया कि 2013-14 के दौरान दिसम्बर,13 तक राज्य में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण का प्रतिशत 6.43% रहा।

अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय,भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण प्रदान किये जाने पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के लिये राज्य मे अग्रलिखित 16 कस्बे/शहर चिन्हित किये है:-

- चुरु,राजगढ,रतनगढ,सरदारशहर,सुजानगढ (चुरु जिला)
- नागौर,लाडनू,मकराना (नागौर जिला)
- झुंझुनू,नवलगढ(झुंझुनू जिला)
- सीकर,फतेहगढ(सीकर जिला)
- टोंक (टोंक जिला)

- गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर जिला)
- बांसवाडा (बांसवाडा जिला)
  निम्बाहेडा (चित्तोडगढ जिला)

<u>एजेण्डा क्रमांक – 6: Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) :</u>

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):
सदन को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2013-14 के लिए 15950 लाभार्थियो को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जबकि वर्ष के दौरान दिसम्बर-13 तक कुल 18891 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमे से 65% प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा रोजगार प्राप्त किया गया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने RSETI/RUDSETIs को पर्याप्त Infrastructure उपलब्ध करवाया जाये पर बल दिया तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्वयं का काम धन्धा/व्यवसाय चालू करने के लिये क्रेडिट लिंकेज से जोडने का आग्रह किया । **श्री आनन्दी लाल (**SPC-Rajasthan) **ने** 70% सैटलमेण्ट रेट मे से 50% सैटलमेण्ट क्रेडिट लिंकेज द्वारा प्राप्त करने का आग्रह किया ।

Financial Literacy Centers (FLCs):
राज्य मे 48 **FLCs** केन्द्र स्थापित किये जा चिके है व इन केन्दों द्वारा समय-समय पर जागरुकता कैम्प,रात्री चौपाल व बैठकों के माध्यम से एक बडे वर्ग को वित्तीय साक्षरता मुहैया करवायी जा रही है।

सदन को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य मे FLCCs द्वारा कुल 1355 आउटडोर एक्टिविटिज(Activities) की गयी जिनमे 96893 व्यक्तियों ने सहभागिता की ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 7: Performance under CGTMSE</u>:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य में 484 करोड़ के 6446 प्रकरणों को CGTMSE योजना के तहत कवर किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 8: शिक्षा ऋण</u>: चालू वित्त वर्ष 2013-14 के लिये MOF द्वारा निर्धारित 73637 खातों मे कुल बकाया राशि रु.1698.55 करोड के लक्ष्यों के पेटे प्राप्ति(Achievment) 63035 खातों में बकाया राशि रु.1453.77 करोड रही ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 9:Rajiv Rinn Yojana- Housing to Urban Poor:</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा ISHUP योजना के 30.09.2013 को बन्द होने तथा इसके स्थान पर 01.10.2013 से **"राजीव ऋण योजना"(Rajiv Rinn Yojana**) के प्रारम्भ होने व योजना का विवरण सभी सदस्य बैकों को प्रेषित कर दिये जाने से सूचित किया गया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक–10: वसूली:</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि 31.12.13 को राज्य मे 65837 **मामले** वसूली हेतु **RACO ROD Act के** तहत बकाया हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं तहत बकाया की वसूली स्टेट ड्यूज की तरह करने के लिये PDR Act मे आवश्यक संशोधन करने हेतु वित्त/राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से पुनः विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

NPA के उच्च स्तर को देखते हुये **अध्यक्ष महोदय ने** राज्य सरकार के अधिकारियों से संयुक्त वसूली Compaign आयोजित करने का आग्रह किया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 11:</u>

<u>SLBC Website:</u> सभी बैंक सदस्यों से तिमाही समाप्ति के 15 कार्य दिवस में आवश्यक सूचना/आंकड़ो को एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का अनुरोध किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 12-अन्य मामले-</u>

अध्यक्ष महोदय द्वारा अंत में सभी सदस्यों से बैको की सभी शाखाओं मे ऑन साइट एटीम (ATM) स्थापित करने, पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड जारी करने,सेवा क्षेत्र गांवों का Sub Service Area के आधार पर कवरेज करने, अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण में उत्तरोत्तर वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

****

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 14.02.2014 को आयोजित 120वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
संयोजक बैंक			
1	श्री पी.श्रीनिवास	कार्यकारी निदेशक	बैंक ऑफ बड़ौदा
2	श्री एल एम अस्थाना	संयोजक, एस.एल.बी.सी.राजस्थान एवं महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय रिजर्व बैंक			
1	डॉ.सत्येन डेविड	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री जे.के.बागड़ी	महाप्रबन्धक आर.पी.सी.डी.	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
3	श्री जय प्रकाश	सहायक महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
नाबार्ड			
1	डॉ.राजेन्द्र कुमार	मुख्य महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	डॉ.अजय के.सूद	उप महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि			
1	श्रीमति राजेश यादव	निदेशक	महिला अधिकारिता,राज.सरकार जयपुर
2	श्री आर.एस.जाटोलिया	महाप्रबन्धक	SJED
3	श्री एस.आर.कटेवा	परियोजना निदेशक (एस.जे.एस.आर.वाई)	स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार
4	डा. एस.एस.छिलर	निदेशक	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
5	श्री ओ.पी.जैन	उप महाप्रबन्धक	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान सरकार(RGAVP)
6	श्री आर.सी.अग्रवाल	नोडल अधिकारी	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान सरकार(RGAVP)
7	शीला के.चौधरी	उप निदेशक	निदेशालय, एम.एस.एम.ई,जयपुर
8	के.सी.अग्रवाल	संयुक्त सचिव	कृषि, राजस्थान सरकार
9	डा. शीतल शर्मा	अतिरिक्त निदेशक	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
10	श्री टी सी.बाचोलिया	ए.ओ.	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
11	श्री आर. के. अमेरिया	संयुक्त निदेशक	आयुक्त उद्योग
12	श्री आर.के.लाम्बा	संयुक्त निदेशक	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
13	श्री एस.सी.डालोदिया	FA & CAO	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
14	श्री वी.पी.सिंहल	रिसर्च अधिकारी	अनु.-जनजाति राष्ट्रीय आयोग, जयपुर
15	श्री एम.पी.मीना	प्रबन्धक	आर.एस.सी.डी.सी.
16	श्री आर.सोलंकी	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

			लि.राजस्थान सरकार
17	श्री बी.एस.जाट	ज्वाइंट सेक्रेटरी प्लानिंग	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
18	श्री एम.के.कुमावत	ज्वाइंट डायरेक्टर आयोजना(आई.एफ.)	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
19	एम.अरोडा	A.D. SHG,WE	महिला एवं बाल विकास विभाग,राज.सरकार
20	श्री वी.के.दाधीच	मैनेजिंग डायरेक्टर	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड
21	श्री एस.एस.दाधीच	ए.ओ.आर.	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड
22	आनन्दी लाल	स्टेट प्रोजेक्ट समंवयक	आरसेटी समंवयक सेल(एमओआरडी)

बैंक, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
23	श्री जे.के.बागड़ी	महाप्रबन्धक आर.पी.सी.डी.	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
24	श्री जय प्रकाश	सहायक महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
25	श्री राजीव अग्रवाल	सहायक महाप्रबन्धक	नाबार्ड,जयपुर
26	श्री आर.सी.खुल्बे	महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
27	श्री एस.पी.हमतान	उप महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
28	श्री एन.के.अरोरा	महाप्रबन्धक	पंजाब नेशनल बैंक
29	श्रीमती अल्का गोतम	महाप्रबन्धक	अपेक्स को-आपरेटिव बैक जयपुर
30	डॉ. एम.एस.फोगाट	अध्यक्ष	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
31	श्री डी.के.जैन	महाप्रबन्धक	मरूधरा ग्रामीण बैंक
32	श्री एम.के.अवस्थी	मुख्य प्रबन्धक	मरूधरा ग्रामीण बैंक
33	श्री बी.के.बालिया	महाप्रबन्धक	मेवाड ऑचलिक ग्रामीण बैंक
34	श्री अलख निरंजन	उप महाप्रबन्धक	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
35	श्री शिव राम	सहा.प्रबन्धक	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
36	श्री के.एन.अरोडा	मुख्य प्रबन्धक	ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
37	श्री रविन्द्रनाथ	सहायक महाप्रबन्धक	सिंडिकेट बैंक
38	श्री एच.एल.रावल	उप महाप्रबन्धक	युनियन बैंक ऑफ इंडिया
39	फेनिशा सर्राफ	सहायक प्रबन्धक	युनियन बैंक ऑफ इंडिया
40	श्री विवेक कौल	सहायक महाप्रबन्धक	युको बैंक
41	श्री बी.एल.चौधरी	वरिष्ठ प्रबन्धक	युको बैंक
42	श्री आर.के.काला	सहायक महाप्रबन्धक	एस.एल.बी.सी., बैंक ऑफ बड़ौदा
43	श्री जी.एल.मानावत	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
44	श्री माधो राम	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
45	श्री गुरमीत सिंह	सहायक महाप्रबन्धक	आई.डी.बी.आई. बैंक

46	श्री फरीद अहमद	उप महाप्रबन्धक	कॉर्पोरेशन बैंक
47	श्री एस.के.शर्मा	सहायक महाप्रबन्धक	इलाहाबाद बैंक
48	श्री प्रकाश छबडिया	डिविजनल मैनेजर	केनरा बैक
49	श्री नरेन्द्र सिंह	प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावेन्कोर
50	श्री आर.जे.एस.बक्शी	मुख्य प्रबन्धक	पंजाब & सिन्ध बैंक
51	श्री राजेश इंगला	मुख्य प्रबन्धक	बैंक ऑफ इंडिया
52	श्री अजय कुमार	सहायक महाप्रबन्धक	इण्डियन बैक
53	श्री पी.पी.सिंह	सी.आर.एम.	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
54	श्री हर्ष मेहता	मुख्य प्रबन्धक	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
55	श्री बी.डी.उपाध्याय	मुख्य प्रबन्धक	देना बैंक
56	श्री मोहित शाहनी	स्टेट हैड	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
57	श्री ईश्वर सिंह शेखावत	अंचल समंवयक	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
58	श्री जितेन्द्र शुक्ला	क्षेत्रीय हैड एफ.आई.	आई. सी. आई. सी. आई. बैंक
59	श्री सन्दीप कु.	डी.वी.पी.	एक्सिस बैंक
60	श्री जैशन टी. जे.	वरिष्ठ प्रबन्धक	कैथोलिक सिरियन बैंक
61	अजीत किशोर	अंचल प्रमुख	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
62	श्री एस.मिश्रा	वरिष्ठ प्रबन्धक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
63	श्री आर.के.मीणा	वरिष्ठ प्रबन्धक	केनरा बैक
64	श्री रमेश पाटोदी	प्रबन्धक	अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैक
65	श्री आर.सी.शर्मा	वरिष्ठ प्रबन्धक	राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक
66	श्री जितेन्द्र बोदानी	वरिष्ठ प्रबन्धक	कोटक बैंक
67	श्री डोन बासव	प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
68	श्री थाम्पा सीवी	मुख्य प्रबन्धक	फैडरल बैक
69	श्री तेज सिंह	वरिष्ठ प्रबन्धक	एक्सिस बैक
70	श्री आर.एस.राठोड	प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
71	वी.के.अग्रवाल	मुख्य प्रबन्धक	इण्डियन ओवरसीज बैक
72	अमरीता डी.	प्रबन्धक	इण्डियन ओवरसीज बैक
73	श्री आरती दीक्षित	सहायक प्रबन्धक	साऊथ इंडियन बैंक
74	श्री ए.के.राथ	शाखा प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
75	श्री हरिन्द्र सिंह	अधिकारी	पंजाब & सिन्ध बैंक
76	श्री एस.दायमा	ए.वी.पी.	रत्नाकर बैंक
77	श्री के.पी.सिंह	क्षेत्रीय प्रबन्धक	नेशनल बीमा कम्पनी,जयपुर
78	श्री अनिल माथुर	कंसलटेण्ट	भारतीय कृषि बीमा कंपनी,जयपुर
79	श्री गी.सी.गुप्ता	एरिया मैनेजर	भारतीय कृषि बीमा कंपनी,जयपुर
80	श्री रमेश गोयल	प्रबन्धक	युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी,जयपुर्

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx